

ल.अं./49/एस.एल.बी.सी./224

15.07.2023

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०) के समस्त सदस्यों को पत्र


महोदय/ महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2023 त्रैमासांत की समीक्षा बैठक दिनांक 26.06.2023 का कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 26.06.2023 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०) की मार्च 2022 त्रैमासांत की समीक्षा बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,


(रोहित जिनीवाल)

उप महाप्रबन्धक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2023 तिमाही की दिनांक 26.06.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2023 तिमाही की समीक्षा बैठक दिनांक 26.06.2023 को श्री सुरेश खन्ना माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री अजय कुमार खुराना, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी। बैठक में श्री राजशेखर, सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, श्री प्रांजल यादव, सचिव, MSME, उत्तर प्रदेश शासन, श्री समीर वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ० प्र०, श्रीमती श्रद्धा ठाकुर, महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ, श्री संजय कुमार डोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ, श्री राजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०) सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा सहभागिता की गयी। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री राजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ० प्र० ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए समस्त बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग व कार्यों की सराहना की। उन्होंने प्रदेश में की जा रही बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की अद्यतन प्रगति से सभा को अवगत कराया।

गत बैठक दिनांक 28.03.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि के उपरांत, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मानकों पर प्रदेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया:-

- प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मार्च 2022 में क्रमशः 3.75 करोड़ एवं 1.13 करोड़ नामांकन किये गये जो मार्च 2023 में बढ़कर क्रमशः 4.70 करोड़ एवं 1.65 करोड़ हो गये हैं। हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि 31.03.2023 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सर्वाधिक नामांकन के साथ हमारा प्रदेश पूरे भारत वर्ष में प्रथम स्थान पर है।
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में अब तक 81.52 लाख लोगों को नामांकित किया जा चुका है तथा 7 जून 2023 को PFRDA द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०) को "Citizen Choice H1 Campaign" में Par Excellence Award दिया गया।
- कुल 8.67 करोड़ खाते खोलते हुए देश में खोले गये कुल 48.76 करोड़ जन धन खातों में 17.78 % हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश "प्रथम स्थान" पर है।
- मार्च 2023 तक प्रदेश में बैंकों का कुल व्यवसाय ₹ 24 लाख 09 हजार करोड़ रहा है जिसमें से जमा राशि ₹ 15.58 लाख करोड़ व अग्रिम ₹ 8.50 लाख करोड़ है जो मार्च 2022 की तुलना में क्रमशः 13.20 %, 11.60% व 16.27% अधिक है।

- चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक ऋण योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्य ₹ 2,94,988 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,00,430 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए मार्च 2023 तिमाही तक 102% की उपलब्धि हासिल की गयी है, उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रथम बार वार्षिक ऋण योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्त किये गए हैं। हमारे प्रदेश में MSME Sector के अन्तर्गत कुल आवंटित लक्ष्य ₹. 78,360 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,50,032 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए मार्च 2023 तिमाही तक 191% की उपलब्धि हासिल की गयी है। साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल आवंटित लक्ष्य ₹. 1,88,574 के सापेक्ष ₹ 1,39,008 करोड़ का ऋण वितरण हुआ है जो 74% की उपलब्धि दर्शाता है।
- पी. एम. स्वनिधि पोर्टल के अनुसार प्रदेश को आवंटित कुल लक्ष्य 8,30,000 के सापेक्ष दिनांक 22.05.2023 तक कुल 11,98,950 एवं 11,74,643 (144%) स्ट्रीट वेन्डर्स को योजनांतर्गत क्रमशः ऋण स्वीकृत एवं वितरण किया जा चुका है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अवगत कराया कि हमारा प्रदेश योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र, स्वीकृत एवं वितरण के मामले में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है।
- वित्तीय वर्ष 2022- 23 के दौरान समस्त हितधारकों के समन्वित प्रयासों से सरकार प्रायोजित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि में शत प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल किया गया है जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु विभिन्न योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भी मैं समस्त बैंकों व अन्य हितधारकों का आह्वान करता हूँ।
- वर्तमान में प्रदेश में 2,01,587 बैंकिंग केन्द्रों का विशाल नेटवर्क आम जन तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है जिसमें 19,538 बैंक शाखाएं, 18,866 ए.टी.एम. एवं 1,63,183 बैंक मित्र (35266बी सी सखी) शामिल हैं। वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत तय किये गए मानक जिनमें प्रदेश के समस्त केन्द्रों को -5- km की परिधि के अन्दर CBS enabled बैंकिंग outlet से बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य को पूर्ण करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है
- प्रदेश सरकार द्वारा RC Filed cases में Recovery हेतु निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने पुनः प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि सरफेसी के अंतर्गत लम्बित मामलों में वसूली हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
- प्रदेश में 10-12 फरवरी तक Global Investors Summit 2023 का आयोजन किया गया, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश को 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करी कि Summit के द्वारा प्रदेश के विकास को एक नयी गति मिलेगी।
- मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 54.54% रहा है जो तिमाही मार्च 2022 के स्तर 52.38% से 2.16% अधिक है।
- प्रदेश में बैंकों के कुल अग्रिम के सापेक्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 4.89 लाख करोड़ (57.60%), MSME क्षेत्र में ₹ 1.68 लाख करोड़ (20.00%) व कमज़ोर वर्ग में ₹. 1.72 लाख करोड़ (20.33%) अग्रिम रहा है जो RBI के निर्धारित मानक क्रमशः 40%, 20% व 12% से अधिक है।
- BC सखी प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश में अब तक ₹ 13 हजार करोड़ मूल्य के 8 करोड़ से अधिक के transactions हुए हैं।



अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री अजय कुमार खुराना, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सर्वप्रथम प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, का बैठक में पधार कर अपना मार्गदर्शन देने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभा में उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यों का अभिवादन करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य की आर्थिक गतिविधियों तथा विभिन्न मानकों में प्रदेश में हुई प्रगति से सभा को निम्नवत अवगत कराया :

- कोविड से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy) के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध ने गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है, युद्ध के कारण आज विश्वभर विशेषकर यूरोपियन देशों में फ्यूल गैस तथा कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए हैं, साथ ही साथ logistics एवं supply chain भी बुरी तरह से प्रभावित है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत प्रगति देखी जा रही है भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी विकास दर 6.4% रहने का अनुमान है।
- वर्तमान परिदृश्य (present scenario) में मुद्रास्फीति (Inflation) तथा आर्थिक गतिविधियों (economic activities) के मध्य संतुलन बनाना Monetary Policy के समक्ष एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹24.39 लाख करोड़ रुपये के Gross State Domestic Product के साथ भारत के शीर्ष राज्यों में अपना स्थान रखता है। प्रदेश न केवल कोविड महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों का डट कर मुकाबला किया है बल्कि इसके कारण उत्पन्न विषम आर्थिक स्थितियों से अपनी सुदृढ़ नीतियों के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा तीव्र गति से विकास कर रहा है।
- प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों जैसे कि U P Investor Summit, Establishment of Defense Corridor, Development of New Expressways, Developing New Airports इत्यादि कार्यक्रमों का ही परिणाम है कि प्रदेश में निवेश व रोजगार के असीम अवसर उत्पन्न हुए हैं।
- एक जनपद एक उत्पाद (One District One Product) प्रदेश सरकार की अनूठी योजना है जिसने प्रदेश के पारंपरिक उद्योग (traditional industry) धंधों को एक नए पहचान दी है इसकी सार्थकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस योजना को पूरे देश में लागू किये जाने का निर्णय किया गया है। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के कारण ही विगत वर्ष से 2.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए इस वर्ष प्रदेश का ऋण जमानुपात 54.54% रहा।
- प्रदेश के समग्र विकास (Holistic Development) हेतु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 6.9 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में ₹ 55,000 करोड़ का प्रावधान expressways, roads तथा नए flyover इत्यादि के निर्माण हेतु किया गया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक शहर कानपुर तथा आगरा में मेट्रो रेल सुविधा हेतु क्रमशः ₹ 585 करोड़ एवं ₹ 465 करोड़ का आवंटन किया गया है जो सरकार की basic infrastructure में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं को विस्तार देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा "ONE GP ONE BC" कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 58,000 बी. सी. सखी की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। बी. सी. सखी के प्रशिक्षण एवं प्रमाणिकरण (Training & Certification) के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बी. सी. सखी की नियुक्ति की जायेगी।

- वार्षिक ऋण योजना (Annual Credit Plan) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में किये गए कुल ऋण वितरण रु 2,12,934 करोड़ के सापेक्ष (vis a vis) मार्च'23 को समाप्त तिमाही में रु. 3,00,430 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है, जो कि गत वर्ष के तुलना में रु 87,496 करोड़ अधिक है तथा आवंटित लक्ष्य (allocated targets) रु 2,94,988 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 102% की उपलब्धि दर्शाता है, उन्होंने सभा को बताया की प्रदेश में प्रथम बार वार्षिक ऋण योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्त किया गया है।
- PFRDA द्वारा SLBC (U.P) को गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु "AWARD OF PAR EXCELLENCE" से सम्मानित किया गया है।
- उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा की गैर निष्पादित आस्तियों (Non Performing Assets) कि संख्या प्रदेश में वित्तीय संस्थानों के लिए मुख्य चुनौती बनी हुई है विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण के अंतर्गत अत्यधिक NPA (> 40%) है। जिसका प्रमुख कारण गन्ना कृषकों का चीनी मिल द्वारा भुगतान उनके केसीसी खातों में ना करते हुए अन्य खातों में किया जाना है। उन्होंने अनुरोध किया की गन्ना किसानों का भुगतान KCC Link खातों में किया जाये।

(कार्यवाही:संस्थागत वित्त विभाग, राजस्व विभाग)

- SARFAESI Act के अंतर्गत सभी बैंकों के -5784- मामले प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालय में आवश्यक अनुमति हेतु लम्बित है। Pending RCs की वसूली हेतु भी राज्य सरकार का सहयोग अपेक्षित है एवं मुझे आशा है कि इसके लिए Revenue Department द्वारा जो portal निर्मित किया गया है वह प्रभावी सिद्ध होगा।

(कार्यवाही:संस्थागत वित्त विभाग)

अंत में उन्होंने एक बार पुनः माननीय वित्त मंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और प्रदेश सरकार के समस्त विभागों के प्रमुखों व वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया, और सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाये दी।

श्रीमती श्रद्धा ठाकुर, महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ, ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का हार्दिक अभिनन्दन किया, साथ ही प्रदेश सरकार, समस्त बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों के अधिकारीगण का अभिवादन करते हुए प्रदेश में बैंकिंग विस्तार पर किये गए कार्यों की सरहना की।

उन्होंने सभी बैंकों से निष्क्रिय BC की स्थिति को नियमित monitor करने तथा BC certification के कार्य में तेज़ी लाने को कहा।

ऋण जमानुपात पर चर्चा करते हुए उन्होंने प्रसन्नत व्यक्त करते हुए सभा को अवगत कराया कि मार्च 23 में प्रदेश का ऋण जमानुपात 54.54% रहा जो कि मार्च 22 में 52.38% से 2.16% अधिक है, यद्यपि प्रदेश में -13- जिलों का ऋण जमानुपात 40% से कम है।

सभा को अवगत कराया की गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा 05.06.2023 को वित्तीय समावेशन की प्रगति को monitor करने हेतु "Antardrashti" नामक एक dashboard की स्थापना से अवगत कराया। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया की इस dashboard पर समयबद्ध तरीके से सूचना उपलब्ध कराये।

उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक unclaimed deposits (रु 4,580 करोड़) उत्तर प्रदेश में है जो कि एक चिंता का विषय है। महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक महोदय ने सभी बैंकों से एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करने को कहा जिसके द्वारा परिपक्वता के समय ग्राहक को उसकी सूचना प्राप्त हो सके। इसी क्रम में RBI द्वारा "100 days 100 pays" अभियान

चलाया जा रहा है, जिसमें unclaimed deposits को उनके legal उत्तराधिकारियों को दिए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

(Action: समस्त बैंक)

Annual Credit Plan के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त किये जाने पर आप ने समस्त बैंकों को बधाई देते हुए कहा कि ऋण हेतु कृषि तथा MSME क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने कि जरूरत है

उन्होंने सभी अग्रणी बैंकों को निर्देशित किया की प्रदेश के सभी जिलों में Lead Districts Managers (LDMs) की पदस्थापना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

(Action: समस्त लीड बैंक)

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का बैठक में पधारने हेतु आभार व्यक्त किया तथा सभा में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों का अभिवादन किया। उन्होंने सभा को अवगत कराया कि समस्त बैंकों के प्रयासों से प्रदेश के इतिहास में चालू वित्तीय वर्ष में Annual Credit Plan के अंतर्गत 102% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है ।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश में -500- Aspirational Block की घोषणा की थी, जिनमें से -100- Block उत्तर प्रदेश में है इन 100 Blocks में जिनका औसत प्रदेश के औसत से कम है उनमें मुद्रा लोन आदि हेतु क्रेडिट कैम्पस लगाये जाये ।

सभा को अवगत कराते हुए आप ने बताया कि माननीय मुख्य सचिव महोदय ने -13- जिलों में, जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है, उनमें विशेष शिविर लगाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि दिसम्बर 2023 तक इन सभी जिलों का ऋण जमानुपात 40% से अधिक करने का लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ।

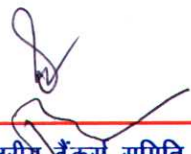
अन्तर्राज्य परिषद्, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्रदेश में शेष -243- बैंक शाखा रहित केन्द्रों पर शाखा खोलने पर चर्चा करते हुए इन केन्द्रों पर IPPB/कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खोलने हेतु कहा ।

उन्होंने कहा कि KCC के अंतर्गत Animal Husbandry, तथा Fisheries में क्रेडिट कम है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु किये जा रहे विभिन्न प्रयासों विशेषकर क्रेडिट आउटरीच कैम्पों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु बैंकों की प्रशंसा की।

उन्होंने अवगत कराया कि बैंकों में NPA की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारियों को बैंकों के साथ समन्वय हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री एस. के. डोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने संबोधन में समस्त सहभागियों का अभिवादन करते हुए प्रदेश में गत कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह हेतु किये गए कार्य की सराहना की तथा निम्न मुद्दों की और समस्त सभाजनों का ध्यानाकर्षण किया:-

- उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का राज्य बनाने हेतु प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने हेतु सभी बैंकर्स को पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु आहवाहन किया।
- ACP में लक्ष्य प्राप्त किये जाने पर उन्होंने सभी बैंकों को बधाई दी ।



- सरकार के द्वारा प्रदेश में आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु व्यापक कार्य किया जा रहा है, अतः सभी बैंकों को इसका लाभ लेते हुए long term lending बढ़ाने हेतु प्रयास करने चाहिये ।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम C:D ratio पर चिंता व्यक्त करते हुए आप ने इस में सुधार हेतु किसान गोष्ठी, स्पेशल camps इत्यादि लगाने को कहा ।
- उन्होंने कहा कि आज समय की आवश्यकता है कि Green Financing को बढ़ावा दिया जाये जिसके अन्तर्गत organic farming, solar energy pump sets, wind mills, bio gas plants आदि में फाइनेंसिंग बढ़ाने की ज़रूरत है ।
- उन्होंने कहा की देश में क्रेडिट-GDP अनुपात 50% है, जबकी प्रदेश में ये अनुपात 38% है, जिसको बढ़ाये जाने की ज़रूरत है ।

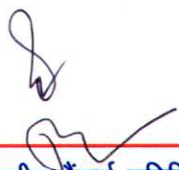
श्री राजशेखर, सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, ने अपने संबोधन में कहा कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को \$1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में प्रगति के बिना सम्भव नहीं है। अतः इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, यद्यपि Annual Credit Plan के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 कृषि के अंतर्गत 74% लक्ष्य प्राप्ति पर उन्होंने सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये पिछले वित्तीय वर्ष के आपेक्षा 8% अधिक है ।

कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु आप ने agriulture infrastructure तथा food processing units पर ध्यान देने का आग्रह किया ।

श्री प्रांजल यादव, सचिव, MSME, ने कहा कि कृषि के बाद MSME क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है । फ़रवरी 2023 में आयोजित Global Investors Summit 2023 में सर्वाधिक MoU, MSME क्षेत्र में ही हुए है । ODOP पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा की इसके अंतर्गत स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या कम है साथ ही स्वीकृत खातों में ऋण वितरण की कार्यवाही अपेक्षानुरूप नहीं है, जिसके ऊपर ध्यान दिए जाने कि तत्काल आवश्यकता है ।

श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के विकास में बैंकों की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सभा में उपस्थित प्रदेश सरकार एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण को निम्नवत सम्बोधित किया:

- एमएसएमई सेक्टर प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक सशक्त माध्यम है। अतः इस क्षेत्र से सम्बन्धित सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिक से अधिक वित्त पोषण की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा पी.एम. स्वनिधि योजनांतर्गत प्रदेश में अच्छा कार्य किया गया है। साथ ही समस्त बैंकों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र वितरण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**
- उन्होंने समस्त बैंकों का अधिकाधिक स्वयं सहायता समूहों को लिकेंज प्रदान करने हेतु आह्वान किया।
- सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जाना चाहिए साथ ही लम्बित आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करने हेतु बैंकों को निर्देशित किया।



- प्रदेश के ऋण जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत तक पहुँचाने हेतु बैंकर्स को प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश के पूर्वी जनपदों के ऋण जमानुपात का स्तर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के जनपदों के ऋण जमानुपात को प्रदेश स्तर पर लाने हेतु ऋण शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोगों को ऋण प्रदान कर लाभान्वित किया जा सके व इन जनपदों के साथ-साथ प्रदेश के ऋण जमानुपात में भी बढोत्तरी सम्भव हो सके।

(कार्यवाही: समस्त बैंक व यूनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया: समन्वयक, ऋण जमानुपात हेतु उप-समिति)

- उन्होंने कहा कि सभी बैंक अच्छे ऋण आवेदनों को लम्बित ना रखते हुए उनका निस्तारण ज़ल्द से जल्द किया करे।
(कार्यवाही: समस्त बैंक)
- Unclaimed deposits हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलाये जा रहे "100 days 100 pays" अभियान कि सरहाना तथा इसको सफल बनाने का आहवाहन किया।

अंत में उन्होंने सभी हितधारकों को समन्वित रूप से प्रदेश के ऋण जमा अनुपात को अखिल भारतीय स्तर पर लाने तथा आम जन तक सुलभतापूर्वक ऋण सुविधा पहुँचाने हेतु प्रयास करने का आहवाहन किया ताकि देश की विकास गाथा में हमारा प्रदेश अहम भूमिका का निर्वहन कर सके, तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित \$1 trillion के लक्ष्य को ज़ल्द से ज़ल्द प्राप्त किया जा सके।

बैठक के अंत में श्री पंकज त्रिपाठी, महाप्रबन्धक, इंडियन बैंक, के द्वारा बैठक में पधारे श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश, शासन के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों तथा बैंको से पधारे प्रमुखों व पदाधिकारियों व अन्य समस्त सहभागियों का विशेष आभार व्यक्त किया तथा उनके अमूल्य मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद दिया।

